due from 1st July, 1991 would be calculated thereafter.

(c) Under the existing orders, the instalment of Dearness Allowance due from 1st July is payable with the salary of September.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया इत्यादि द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण का वितरण

1304. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन कृषकों, कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 1988 से लेकर आज तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं और इससे सम्बद्ध बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं ;

(ख) इस संबंध में प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है कितने आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं तथा इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ऋण देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और कुछ दलालों ने आवेदकों से कमीशन भी लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्जदारों को दलालों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली उन किसानों, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित श्रेणी-वार सूचना नहीं रखती जिन्हें किसी राज्य विशेष में बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं । यह प्रणाली प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूचना भी नहीं रखती है । अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों से गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के कमजोर वर्गों को कुल बकाया राशि की सूचना भेजने के लिए कहा जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम प्रदान करने के लिए सभी बैंकों को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाया जाना चाहिए । बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्र या तो सीधे ही आवेदकों से प्राप्त होते हैं या राज्य के प्रायोजक एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और तदनुसार उन्हें मंजूर किया जाता है । ऋणों के संवितरण में देरी या किसी बिचौलिए द्वारा ऋण-कर्ताओं को परेशान किए जाने से संबंधित बैंकों में प्राप्त शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा जांच की जाती है ।

Posts of P.G.T. in Central School, Moscow

1305. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya, Moscow had been started in 1987 and posts of PGTs in Science and humanities had been sanctioned therefor;

(b) if so, whether it is also a fact that the post of PGT (History) has remained unfilled for the last four years and if so; and

(c) what steps have been taken or are contemplated to fill the vacancy?